

प्रेषक,

मनोज चन्दन

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून

दिनांक 28 जनवरी, 2014

विषय:- वन विभाग के अनुदान सं-27 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 के आयोजनेतर पक्ष की "वन संचार साधन-पुल टेलीफोन तथा भवन" योजना में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश सं0-284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून के प0सं0 नि0-583/3-2(आयोजनेतर-वन संचार साधन), दि0 26 सितम्बर, 2013 एवं प0सं0 नि0-674/3-2 (आयोजनेतर-वन संचार साधन), दि0 09 अक्टूबर, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के आयोजनेतर पक्ष की "वन संचार संचार साधन-पुल, टेलीफोन तथा भवन" योजना में चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये प्राविधानित आय-व्ययक के सापेक्ष शासनादेश सं0-858/X-2-2013-12(45)/2012 दि0 06 जून, 2013 द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹ 50,00,000/- (₹ पचास लाख मात्र) के पश्चात् अवशेष धनराशि ₹ 35,00,000/- (₹ पैंतीस लाख मात्र) व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-284/XXVII(1)/2012 दि0 30 मार्च, 2013 तथा शासनादेश सं0-413 /XXVII (1)/2012 दि0 10 जून, 2013 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण/मासिक प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किशतों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
3. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी तथा व्यवसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित इकाई में सक्षम स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो के अन्तर्गत ही रहेगी।
4. आपके निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
5. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण निर्धारित बी0एम0 प्रपत्र पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
6. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति में अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाय और यह सुनिश्चित किया जाये कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाय और तदनुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

7. मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं०-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दि० 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।
 8. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
 9. धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
 10. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1401270186 है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे।
- 2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक 2406 वानिकी तथा वन्य जीवन 01 वानिकी 070 संचार तथा भवन 03-00 वन संचार साधन-पुल, टेलीफोन तथा भवन, मानक मद 29-अनुरक्षण के नामे डाला जाएगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कापी भी संलग्न की जा रही है।
- 3- ये आदेश वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-284/XXVII(1)/2012 दि० 30 मार्च, 2013 तथा शासनादेश सं०-413 /XXVII (1)/2012 दि० 10 जून, 2013 के आलोक में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज चन्दन)
अपर सचिव

संख्या- 178 /X-2-2014, तददिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
10. बजट रानकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
11. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

(मनोज चन्दन)
अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20132014

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - 178 /X-2-2014-12(47)/2012

अनुदान संख्या - 027

अलोटमेंट आई डी - S1401270186

आवंटन पत्र दिनांक -24-Jan-2014

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

- 1: लेखा शीर्षक 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन 01 - वानिकी
070 - संचार तथा भवन 03 - वन संचार साधन-पुल,टेलीफोन तथा भवन
00 - वन संचार साधन-पुल,टेलीफोन तथा भवन

Non Plan Voted			
मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
29 - अनुरक्षण	5000000	3500000	8500000
	5000000	3500000	8500000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

3500000